तापमान

भोपाल	21.0°	35.0°
इंदौर	18.0°	36.0°
जबलपुर	21.0°	35.0°
ग्वालियर	25.0°	37.0°
सागर	21.0°	34.0°

नईदुनिया

वर्ष- 80
(भोपालः वर्ष 41 अंक 308, पृष्ठ 12)
आश्विन, कृष्ण दशमी संवत् 2083
मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026
कीमतः 3:00 रुपये

www.naidunialive.com

भोपाल संस्करण

भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित



राजधानी... मध्यप्रदेश देश की फूड बास्केट बन चुका है ...



खेल... ओलंपिक में सीधे प्रवेश से अब तैयारियों के लिए अधिक ...



व्यापार... समझौता टूटा नहीं, नए विकल्प मिलने पर आगे ...



देश-विदेश... चीन के लिए जासूसी के शक में अमेरिकी ...

ज्ञानेश के निलंबन से 'सुप्रीम' इन्कार

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से जुड़े मामलों में सोमवार को सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग के निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल निलंबित करने का अंतरिम आदेश देने से इन्कार कर दिया, लेकिन चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि यदि रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि जरूरी प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई निर्णय लिया गया, तो संबंधित फैसले पर रोक लगाने या उसे वापस लेने पर विचार किया जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल मीडिया में प्रकाशित खबर के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ निलंबन का अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि किसी खबर के पूरी तरह सही, आंशिक रूप से सही या गलत होने की संभावना हो सकती है। इसलिए पहले चुनाव आयोग का जवाब और संबंधित रिकॉर्ड देखना जरूरी है।

आखिर सच क्या है? फॉर्म-6 में बदलाव, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मंजूरी नहीं दी, सीईसी बोले-कोर्ट की मंजूरी है

चेतावनी- बिना सहमति लिए फैसले हुए तो लग सकती है रोक



फैसले सर्वसम्मत या बहुमत हों...

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के फैसले सामूहिक रूप से लिए जाने चाहिए। तीन सदस्यीय आयोग में निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर होना चाहिए। अदालत ने कहा कि केवल आरोपों के आधार पर यह मान लेना उचित नहीं होगा कि सभी फैसले मुख्य चुनाव आयुक्त ने अकेले लिए। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव कराने और उसकी निगरानी की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। हालांकि, आयोग के फैसलों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यदि कोई निर्णय कानून या संविधान के विपरीत पाया जाता है तो अदालत उस पर रोक लगा सकती है या उसे रद्द कर सकती है।

महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी

मामले को लेकर विपक्ष भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। अप्रैल 2026 में भी ऐसा नोटिस दिया गया था। लोकसभा में प्रस्ताव खारिज हो चुका है, जबकि राज्यसभा में यह अभी लंबित है।

फॉर्म-6 से जुड़े बदलाव पर रार

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने फॉर्म-6 से जुड़े बदलाव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म-6 में किसी संशोधन को मंजूरी नहीं दी है। इससे पहले चुनाव आयोग की ओर से कहा गया था कि एसआईआर के लिए फॉर्म-6 के साथ लगाए गए घोषणा पत्र को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी प्राप्त थी। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दो जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। एक याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग की गई है। दूसरी याचिका भी एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित है।

मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती जयंती पर 143 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी

छह सांदीपनि विद्यालय और 490 सीटर कन्या छात्रावास की घोषणा



नईदुनिया ब्यूरो, खंडवाः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती के दिखाए मार्ग पर मध्यप्रदेश सरकार जनजातीय समुदाय के कल्याण और विकास का नया अध्याय लिख रही है। मुख्यमंत्री सोमवार को खंडवा जिले के हरसूद क्षेत्र के ग्राम छनेरा में रानी दुर्गावती की 502वीं जयंती और तेंदूपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में पहली बार गोंडवाना साम्राज्य के 52 गढ़ों के राजवंशजों का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री ने उन्हें साफा पहनाकर तलवार और स्मृति चिन्ह भेंट किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी दुर्गावती ने प्रजा के सुख को अपना धर्म माना और कृषि, जल प्रबंधन तथा आधारभूत ढांचे को मजबूत किया। उन्होंने रानी दुर्गावती की वीरता और प्रशासनिक क्षमता को याद करते हुए कहा कि उन्होंने 52 युद्ध लड़े और 51 में विजय प्राप्त की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने खंडवा जिले में करीब 143 करोड़ रुपये की लागत के 18 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। उन्होंने खालवा तहसील में छह सांदीपनि विद्यालय, हरसूद में 490 सीट वाला नया कन्या छात्रावास और करीब 161 करोड़ रुपये की लागत से 40 नए जनजातीय छात्रावास बनाने की घोषणा की। आश्रम स्कूलों के विकास के लिए 143 करोड़ रुपये देने की बात भी कही। खंडवा में 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से उच्च तकनीक वाली नर्सरी और जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में खेल परिसर बनाने की घोषणा की गई।

एंटी-प्लेग संस्थान में काम करती थी महिला, अज्ञात निमोनिया की जांच जारी

रूस में अज्ञात संक्रमण से एक की मौत, 200 क्वारंटाइन

मॉस्को, एजेंसीः रूस में एक एंटी-प्लेग अनुसंधान संस्थान में काम करने वाली 28 वर्षीय महिला कर्मचारी की मौत के बाद उसके संपर्क में आए करीब 200 लोगों को चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। महिला की पहचान दर्या शिपिलोवा के रूप में हुई है। वह साइबेरिया स्थित प्रयोगशाला में कार्यरत थी। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, 25 सितंबर को प्रयोगशाला में काम के दौरान जीवित जैविक नमूनों वाली एक टेस्ट ट्यूब टूट गई थी। इसके चार दिन बाद 29 सितंबर को महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन 1 अक्टूबर की रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। टेस्ट ट्यूब में किस तरह का जैविक नमूना था, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ रिपोर्टों में इसे प्लेग से जुड़े नमूने से जोड़ा है।

उत्तरप्रदेश में भाजपा के आठ राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम घोषित

दो महिलाओं समेत पिछड़े और दलित वर्ग के साथ ब्राह्मणों को भी प्रतिनिधित्व

नईदुनिया ब्यूरो, लखनऊः भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार को आठ प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए।

पार्टी ने सभी सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया है। सूची में दो महिलाएं शामिल हैं। प्रत्याशियों में दो ब्राह्मण, एक ठाकुर, तीन पिछड़े और दो दलित वर्ग से हैं। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा को दोबारा राज्यसभा भेजने का मौका नहीं दिया है। मौजूदा सांसद नीरज शेखर, सीमा द्विवेदी, बृजलाल, गीता शाक्य और अरुण सिंह को भी टिकट नहीं मिला। दिनेश शर्मा को अंडमान-निकोबार का राज्यपाल बनाया जा चुका है।

भाजपा के घोषित प्रत्याशियों में बरेली की आंवला विधानसभा सीट से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, प्रयागराज के वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा, भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल, जौनपुर के वरिष्ठ नेता विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत, भाजपा प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार शामिल हैं।

श्रुति गंगवार झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की बेटी हैं। प्रियंका सिंह रावत 2014 में बाराबंकी से भाजपा के टिकट पर लोकसभा सांसद चुनी गई थीं और जिले की पहली महिला सांसद बनी थीं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं। इनमें 10 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को चुनाव होना है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है।

